- कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन क्षेत्र से वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर कीमतों पर जीवीए में किस दर से वृद्धि होने का अनुमान है?
   मात्र 2.8 प्रतिशत
- भारत में कृषि क्षेत्र अपने चिर-परिचित रूप में संवृद्धि की दृष्टि से चक्रीय गति से गुजरता है। कृषि में सकल मूल्य वृद्धि वर्ष 2014-15 में 0.2 प्रतिशत ऋणात्मक से वर्ष 2016-17 में 6.3 प्रतिशत धनात्मक रही। यह क्रमश: कम होकर वर्ष 2018-19 में कितनी रह गई?
- आर्थिक समीक्षा, 2019-20 के अनुसार, राष्ट्रीय आय में इसका योगदान वर्ष 2014-15 के 18.2% से गिरकर वर्ष 2019-20 में कितना हो गया?
   मात्र 16.5% (नोट: यह अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रियाओं एवं संरचनात्मक परिवर्तन को दशांता है।)
- कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भी देश में आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए कृषि सर्वप्रथम व्यवसाय बना हुआ है। वर्ष 2018 में देश के कार्यबल का कितना हिस्सा कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है?
- आर्थिक समीक्षा, 2019-20 के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में पशुधन क्षेत्र में किस दर से वृद्धि हुई है?
   लगभग 8% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से
- वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक की अवधि के दौरान फसलों, पशु और वन क्षेत्र की वृद्धि दरों में कमी-बेशी होती रही, लेकिन मत्स्यपालन क्षेत्र में वर्ष 2012-13 में 4.9 प्रतिशत वृद्धि दर से बढ्कर वर्ष 2017-18 में कितने की तीव्र वृद्धि दशायी है?
- 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि लक्ष्य
   4.0% का था। इस दौरान वास्तविक वृद्धि किस दर से हुई? मात्र 3,6 प्रतिशत
- 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना के ही समान कितना रखा गया था?
   मात्र 4,0 प्रतिशत
- दूध, दालों, जूट और जूट जैसे रेशों के उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। वावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियों, फलों एवं कपास उत्पादन के मामले में इसका स्थान कौन-सा है?

#### सहकारी कृषि

सहकारी कृषि (Cooperative Farming) से आशाय खेती की उस प्रणाली से है, जिसमें कृषक अपने छोटे-छोटे खेतों एवं साधनों को एकत्रित कर संयुक्त रूप से खेती करते हैं और उपज से प्राप्त आय का वितरण धूमि तथा श्रम के अनुपात में कर लेते हैं।

#### सामृहिक कृषि

सामूहिक कृषि (Collective Farming) से तात्पर्य उस कृषि से है, जिसमें किसी राजकीय नीति के अंतर्गत छोटे-छोटे भूखंडों को मिलाकर एक बड़ा भूखंड बना दिया जाता है तथा उस पर कृषि कार्य एक समिति को साँप दिया जाता है, जिसे उस भूखंड का स्वामी माना जाता है। ऐसे भूखंड पर सभी सदस्य कृषि कार्य करते हैं तथा उपज को पारिश्रमिक श्रम के आधार पर मजदूरी के रूप में वितरित किया जाता है।

#### भारत की तीन प्रमुख फसलें

भारत में मुख्यत: तीन फसल मौसम (Crop Seasons) हैं- खरीफ, रवी और जायर। खरीफ फसलों की बुआई जुलाई में होती है और सितंबर के अंत में और अक्टूबर में काटी

मद	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17#	2017-18@	2018-19**	2019-20
आधार की मतों पर सकल मूल्य वृद्धि	6.1	7.2	8.0	7.9	6.9	6.6	4.9
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	5.6	-0.2	0.6	6.3	5.0	2.9	2.8
फसल	5.4	-3.7	-2.9	5.0	3.8	-	-
पशुधन	5.6	7.4	7.5	9.9	7.0	-	-
वानिकी और लड्ठे बनाना	5.9	1.9	1.7	1.4	2.1	-	-
मछली पकड्ना और एक्वाकल्चर	7.2	7.5	9.7	10.0	11.9	-	-

स्रोतः केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा 2019-20 नोटः \*तृतीय संशोधित प्राकलन, ≢ द्वितीय संशोधित प्राकलन, @ प्रथम संशोधित अनुमान पर \*\*सीएसओ द्वारा दिनांक 31 मई, 2019 को जारी किए 2018-19 के वार्षिक राष्ट्रीय आय के तदर्थ अनुमानों और 2018-19 की चौथी तिमाही हेतु सकल घरेलु उत्पाद

1

के तिमाही अनुमानों पर। F: प्रथम अग्रिम अनुमान।

िन्दण MCERT अर्थव्यवस्था सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

समृह/वस्तु	क्षेत्र ( मिलि	यन हेक्टेयर)	उत्पादन ( वि	मेलियन टन)	उपज (किग्रा/हेक्टेयर)	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
खाद्यान	127.5	123.9	285.0	285.0	2235	2299
चावल	43.8	43.8	112.8	116.4	2576	2659
गेहूं	29.7	29.1	99.9	102.2	3368	3507
ज्वार	5.0	3.8	4.8	3.8	960	979
मक्का	7.5	6.9	9.2	8.6	1231	1242
वाजरा	9.4	9.2	28.8	27.2	3065	2966
दलहन	29.8	29.0	25.4	23.4	853	806
चना	4.4	4.8	4.3	3.6	966	751
तूर∕अरहर	10.6	9.4	11.4	10.1	1078	1073
तिलहन	24.5	25.5	31.5	32.3	1284	1265
मूंगफली	4.9	4.8	9.3	6.7	1892	1395
रेपसीड और सरसों	6.0	6.2	8.4	9.3	1410	1499
गन्ना (टन/हेक्टेयर)	4.7	5.1	379.9	400.2	80	78
कपास**	12.6	12.7	32.8	28.7	443	386

स्रोतः आर्थिक और सांख्यिकी निर्देशालय, कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग । आर्थिक समीक्षा 2019-20 \* कृषि फसलें चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार एवं वागवानी फसलें तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार \*\* 170 कि.ग्रा. की गांठें

- भारत में मुख्यत: तीन प्रकार की फसलें होती हैं। उनके नाम क्या हैं?
  - खरीफ, रबी और जायद
- रवी की फसल अक्टूबर में बोबी जाती है, खरीफ की फसलों की बुआई कब होती है?
- अक्टूबर 2007 में शुरू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को तीन भागों में विभाजित किया गया है। ये मिशन कीन-कीन से हैं? - खावल मिशन, गेहं मिशन तथा दाल मिशन
- 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को तीन भागों में विभाजित किया गया था- चावल मिशन, गेहूं मिशन, तथा दाल मिशन। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस मिशन के तहत दो और घटकों को शामिल किया गया। ये दो घटक कौन-कौन से हैं? मोटे अनाज मिशन तथा वाणिन्यिक फसल मिशन
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना में दाल मिशन के तहत उत्पादन का लक्ष्य 2 मिलियन टन से बढ़ाकर 4 मिलियन कर दिया गया। मोटे अनाज मिशन के तहत उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया?
   - 3 मिलियन टन
- वर्ष 2014 में विश्व व्यापार में धारत का कृषि निर्यात और आयात का हिस्सा कितना
   अन्नभश: 2,46 व 1,46 प्रतिशत
- कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात वर्ष 2009-10 में 7.75 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 12.08 प्रतिशत हो गया है। इसी अविध के दौरान कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि आवात 4.90 प्रतिशत से बढ़कर कितना हो गया?
- आर्थिक समीक्षा, 2019-20 के अनुसार, वर्ष 2017-18 में घारत के कुल निर्यात में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का हिस्सा 12.7 प्रतिशत था। यह हिस्सा 2018-19 में कितना हो गया?

जाती हैं। इसके तहत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, निल, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली आदि की फसलें आती हैं। रबी फसलों की बुआई अक्टूबर में होती हैं और उनकी कटाई अप्रैल में की जाती है। इसके अंतर्गत आने वाली फसलों में प्रमुख हैं— गेहं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। जायद के तहत आने वाली फसलें हैं— तरबूज, खरबूज, ककड़ी एवं विधिन्न प्रकार की सब्जियां। ये फसलें कुछ स्थानों पर होती हैं तथा इनकी बुआई एवं कटाई क्रमश: मार्च और जून में होती हैं। ज्ञातव्य है कि चावल और तिलहन खरीफ और रबी दोनों तरह की फसलें हैं।

# सरकारी कृषि

जब सरकार द्वारा सभी भूमियों का स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया जाता है और उन भूमियों पर खेती श्रमिकों की सहायता से सरकारी कर्मचारी करते हैं, तो इस प्रकार की खेती को सरकारी कृषि या राजकीय कृषि (Government Farming) की संज्ञा प्रदान की जाती है।

# फिरण NCERT अर्थव्यवस्था सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

प्रमुख फसलों का उत्पादन (मिलियन टन)							
समूह/बस्तु	1990-91	2000-01	2010-11	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
खाद्यान"	176.4	196,8	244,5	251,6	275.1	285,0	285,0
खरीफ	99.4	102.1	120.9	125.1	138.3	140.5	141.7
रबी	77.0	94.7	123.6	126.5	136.8	144.6	143.2
अनाज्य	162.1	185,7	226,3	235,2	252,0	259,6	261,6
खरीफ	94.0	97.6	113.8	119.6	128.7	131.2	133.1
रबी	68.1	88.1	112.5	115.7	123.2	128.4	128.4
मोटे अनाज"	32.7	31,1	43,4	38,5	43,8	47.0	43,0
खरीफ	27.7	24.9	33.1	28.2	32.4	34.0	31.0
रबी	5.0	6.2	10.3	10.4	11.3	12.9	12.0
दालेंष	14.3	11.0	18.2	16.4	23.1	25,4	23.4
चावत	74.3	85.0	96.0	104.4	109.7	112.8	116.4
गेह्	55.1	69.7	86.9	92.3	98.5	99,9	102.2
ज्वार	11.7	7.5	7.0	4.2	4.6	4.8	3.8
मक्का	6.9	6.8	10.4	8.1	9.7	9.2	8.6
बाजरा	9.0	12.0	21.7	22.6	25.9	28.8	27.2
चना	2.4	2.2	2.9	2.6	4.9	4.3	3.6
तूर	5.4	3.9	8.2	7.1	9.4	11.4	10.1
तिलहन <sup>द</sup>	18.6	18,4	32,5	25,3	31,3	31,5	32,3
मूंगफली	7.5	6.4	8.3	6.7	7.5	9.3	6.7
रेपसीड व सरसों	5.2	4.2	8.2	6.8	7.9	8.4	9,3
गन्श	241.0	296.0	342.4	348.4	306.1	379.9	400.2
कपास"	9.8	9.5	33.0	30.0	32.6	32.8	28.7
जूट व मेस्ता <sup>व</sup>	9.2	10.5	10.6	10.5	11.0	10.0	9.8
जूट	7.9	9.3	10.0	9.9	10.4	9.6	9.4
मेस्ता	1.3	1.2	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4
बागानी कसले	बागानी फसलें						
चाय	0.7	0.8	1.0	1.2	1.3	1.3	1.4
काफी	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	ন্তন
रबड्	0.3	0.6	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7
आलू	15.2	22.5	42.3	43,4	48.6	51.3	53.0

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निर्देशालय, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विश्वाय। टिप्पणी: आर्थिक समीक्षा

क : अनाव, मोटे अनाव एवं रालें सम्मिलित हैं।

ख : चावल और गेहूं सम्मिलित हैं।

मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और जी शामिल है।
 तूर, उड्डर, मूंग, चना, मसूर एवं अन्य दाल सम्मिलित है

 मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, अरंडी, नाइजरसीड, कुसुम्म, सूरजमुखी और सोवाबीन सम्मिलित हैं।

च : 170 कि-ग्रा॰ की गांठें। छ : 180 कि-ग्रा॰ की गांठें।

2017-18 : कृषि एवं वाणिज्यिक फसलें चौथे अग्रिम अनुमान, 2017-18 के अनुसार

2018-19 : कृषि कसलें द्वितीय अग्रिम अनुमान एवं बागवानी कसलें प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार

- बादामी क्रांतिः मसालों का उत्पादन एवं निर्यात
- सुनहरी (Golden) क्रांतिः फल/सेब/ मध्/बागवानी उत्पादन
- सुनहरा रेशा (Golden Fibre) क्रगेतिः जूट उत्पादन

#### नॉर्मन ई. बोरलॉग

अमेरिका में 25 मार्च, 1914 को जन्मे नॉर्मन ई. बोरलॉंग एक जीवविज्ञानी और कृषि विज्ञानी थे। उनको हरित क्रांति का जनक, कृषि का सबसे बड़ा प्रवक्ता और अरबों लोगों के जीवन को बचाने वाला (The Man Who Saved A Billion Lives) कहा जाता है। उनको भूखे विश्व को भोजन महैया कराने के लिए जीवन भर काम करते रहने के लिए 1970 में नोबंल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको 2006 में भारत कं दूसरे सबसे वडं नागरिक सम्मान पर्म विभूषण से भी पुरस्कृत किया गया। बोस्लॉग ने 1986 में 'विश्व खाद्य पुरस्कार' की स्थापना की और पहला विश्व खाद्य प्रस्कार भारत में उनके सहयोगी एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। 12 सितंबर, 2009 को 95 वर्ष की आयु में बोस्लॉग का अमेरिका के डलास में उनका निधन हो गया।

#### प्रसंविदा कृषि

किसी समझौते के तहत कृषि करना, जो दोनों ही उत्पादक (कृषक) तथा उत्पाद के क्रेता को लाभ पहुंचाए, को प्रसोंवदा कृषि (Contract Farming) कहते हैं। समझौता की शर्तों के अनुसार इसके अनेक मॉडल हो सकते हैं, पर सामान्यत: यह देखा जाता है कि प्रसोंवदा का एक पक्ष तो किसान होगा तथा दूसरा पक्ष कम्पनी या संस्था होगी जो कृषि उत्पाद को एक निश्चित बाजार निर्धारित मूल्य पर क्रय करने का सम्झौता करती है तथा कृषक को उत्तम कोटि के बीज, उर्वस्क, सिंचाई, ऋण आदि की पूर्ति करती है। इस प्रकार इस स्थिति में कृषक अपने लिए नहीं, अपनी इच्छा से भी नहीं बल्क प्रसींवदा की दूसरी पार्टी

2019-20

- किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC)

- मध्यमकालीन ऋण वह ऋण है, जो कृषकों को फार्म पर औजार क्रय करने, बैल, दुधारू पशु क्रय करने, भूमि सुधार, बाइ लगाने आदि के लिए स्वीकृत किया जाता है। यह एक से अधिक वर्ष की अविध में परिपक्व होता है तथा ऋण का भुगतान दो या दो से अधिक वर्षों में किया जाता है। इस ऋण के भुगतान की अधिकतम अविध कितनी होती है?
- 1998 में किसानों को उनके पास उपलब्ध भूमि के आधार पर बिना किसी प्रतिभृति गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई?
- कंसीसी योजना पहले केवल उन्हीं किसानों के लिए थी, जिनके पास अपनी कृषि योग्य जमीन थी, लेकिन बाद में उन किसानों के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी और वे दूसरे की जमीन पर खेती का कार्य करते थे। यह कार्ड कितनी अविध के लिए वैध होता है? – 3 वर्ष के लिए
- केसीसी कार्डधारकों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी ग्रशि का बीमा कवर दिया जाता है?
   50,000 रुपथे
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत सभी पात्र एवं इच्छुक किसानों को केसीसी पास बुक के बदले समयबद्ध तरीके से एटीएम-सह-क्रेडिट कार्ड देने की योजना कब शुरू की गई?
   - मार्च 2012 में
- 1974-75 में शुरू प्रायोगिक फसल बीमा योजना आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में तीन फसलों कपास, गेहूं एवं मृंगफली से संबीधत थी। इस योजना को सरकार ने किस वर्ष समाप्त कर दिया?
- पायलट फसल बीमा योजना 1979 में सामान्य बीमा निगम द्वारा शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत शुरू में केवल नगदी फसलों को शामिल किया गयाथा। इसके तहत किस वर्ष खरीफ फसलों को भी सम्मिलित कर लिया गया?
   वर्ष 1982-83
- व्यापक फसल बीमा योजना को 15 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में 1985 में लागू किया गया। इस योजना को सरकार ने किस वर्ष समाप्त घोषित किया?
  - वर्ष 1997 में
- सभी राज्यों में सभी फसलों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (1999-2000) की शुरुआत रवी मौसम से कब की गई?
   अक्टबर 1999 में
- राष्ट्रीय कृषि बीमा यौजना (NAIS: National Agricultural Insurance Scheme)
   का प्रस्ताव में किस वर्ष के केंद्रीय बजट में किया गया?
   वर्ष 1998-99
- राष्ट्रीय कृषि बीमा यौजना केंद्र प्रायोजित योजना है, परंतु इस पर आने वाले व्यय को केंद्र तथा राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात में सामान्य रूप से वहन किया जाता है।
   प्रारंभ इसका क्रियान्वयन सामान्य कृषि बीमा निगम द्वारा किया गया। बाद में इसका क्रियान्वयन किसको सींप दिया गया?
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए भारतीय कृषि बीमा निगम का गठन कब किया गया?
- भारतीय कृषि बीमा निगम को बाद में एक लिमिटेड कम्पनी में बदल कर कब से इसका नाम भारतीय कृषि बीमा निगम लिमिटेड कर दिया गया? - अप्रैल 2003 से
- केंद्रीय बजट 2003-04 में प्रस्तावित राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना, जिसके तहत किसानों को उनकी कुल उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित राशि मिलने की गारंटी होती है, की शुरुआत कब की गई?
- रबी मौसम 2013-14 से किस योजना के लागू होने पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को वापस ले लिया, हालाँकि वर्ष 2013-14 के दौरान कुछ राज्यों को एनएआईएस को क्रियान्वित रखने की अनुमति दी गई? - राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (NCIP)

के निर्देश पर उत्पादन करता है। इस स्थिति में किसानों को, विशेष रूप से छोटे तथा सीमांत किसानों को वे सभी सुविधाएं मिल जाती हैं जो उन्हें व्यक्तिगत स्थिति में नहीं प्राप्त हो पातीं। इसके अंतर्गत कृषक को अच्छी गुणवत्ता का आगत, आवश्यकता पड़ने पर ऋण तथा उत्पाद के लिए सही मुल्य बिना किसी कठिनाई के मिल जाता है। राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 में इस बात पर बल दिया गया कि सरकार प्रत्येक वस्तु की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मॉडल प्रसोविदा विकसित करेगी, सरकार यह देखेगी कि किसी स्थिति में किसान अपनी भूमि के स्वामित्व से अलग नहीं हों। राज्य सरकार भी कृषक मंत्री प्रसर्विदा तैयार करने का प्रयास करेगी।

# शुन्य बजट प्राकृतिक खेती

'शून्य बजट प्राकृतिक खेती' (ZBNF: Zero Budget Natural Farming) 事7 तात्पर्य है बिना किसी ऋण और आदानों पर बिना धन खर्च किए बिना रसायनों के प्रयोग के प्राकृतिक रूप से खेती करना। जेडबीएनएफ का मुख्य उद्देश्य रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को समाप्त करना और अच्छी कृषिविज्ञान परिपाटियों को प्रोत्साहन देना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण एवं प्रकृति के अनुकूल प्रक्रियाओं की सहायता से कृषि उत्पादन करने का है ताकि रसायन कृषि मुक्त उत्पादन किया जा सके। इसके अंतर्गत कम पानी की जरूरत होती है और यह पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में पीकेवीवाई योजना के संशोधित दिशानिर्देशों में विभिन्न जैविक कृषि मॉडलॉ, जैसे ग्राकृतिक खेती, वैदिक खेती, गाय पालन, होमा अविक खंती, शून्य बजट प्राकृतिक खंती आदि को शामिल किया गया है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश जेडबीएनएफ का प्रगतिशील रूप से उपयोग कर रहे हैं। इससे इन राज्यों में आदान लागतों में भारी कमी आई है और पैदावार में वृद्धि हुई है।

# िनरण MCERT अर्थव्यवस्था सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) की तीन घटक योजनाएं हैं- संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना तथा नारियल ताड़ बीमा योजना। एनसीआईपी की कब से शुरुआत की गई? - 1 नवंबर, 2013 से
- मौसम आधारित फसल बीमा योजना की शुरुआत प्रायोगिक तौर पर कब की गई थी?
   खरीफ मौसम 2007
- नारियल उत्पादक राज्यों (केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और पश्चिम बंगाल) में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नारियल ताड़ बीमा योजना की शुरुआत कब की गई?
   वर्ष 2009-10
- मानसून न आने के कारण किसानों को होने वाली क्षति की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने वर्षा बीमा योजना की शुरुआत किस वित्त वर्ष में की? - वर्ष 2004-05
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएआईएस) की जगह 13 जनवरी, 2016 को किस नई योजना की शुरुआत की गई?
   प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

(मौजूदा उपज आधारित एवं फसल आधारित बीमा योजना के तहत लगभग 37 मिलियन (27 प्रतिशत खेती करने वाले) परिवारों को कवर किया गया है।)

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य अगले 3 वर्ष में कितने प्रतिशत फसल को कवर करने का है?
   50 प्रतिशत
- पशुओं की आकस्मिक मृत्यु के कारण हुई हानि के लिए उनके मालिकों को आर्थिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य के साथ 1 फरवरी, 2006 को कौन-सी योजना देश के 100 जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई? - पशुधन बीमा योजना
- पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रारंभ की गई पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना कैसी योजना है?
   केंद्र प्रायोजित
- प्रत्येक फसल के आने से पूर्व सरकार विभिन्न फसलों के लिए मूल्य की घोषणा करती है, जिसका उद्देश्य किसानों को वह आश्वासन प्रदान करना होता है कि अधिक फसल होने पर सरकार अधिक मात्रा में इस कीमत पर किसानों से खाद्यान्न खरीदने को तैयार है। इस कीमत को क्या कहते हैं? - व्यूनतम समर्थन मूल्य
- केंद्र सरकार एक वर्ष में कितनी बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। करती है?
   दो बार (एक बार रबी की फसल हेतु, तो दूसरी बार खरीफ फसल के लिए)
- न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना की शुरुआत 1966-67 में गेहूं के साथ की गई।
   आज कितनी वस्तुओं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है?
   24 फसल
- प्रापण मूल्य हमेशा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रखा जाता है। इसका कारण किसानों को अधिक लाभ का लालच देकर सरकारी भंडार में आवश्यकतानुसार खाद्यान्न की कमी को पूरा करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसलों की बुआई के पहले की जाती है, परंतु प्रापण मूल्य की घोषणा कब की जाती है?

- फसल तैयार होने बाद

- सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं बफर स्टॉक कायम करने के लिए मॉडियों से कृषि उत्पाद की खरीद किस कीमत पर करती है?
   वसुली कीमत
- जिस कीमत पर उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कृषि उत्पादों की खरीद करता
   है, उसे क्या कहते हैं?
- कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के लिए सरकार को संस्तुतियां कौन
  प्रदान करता है?
   कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

## सिंचाईं जल उत्पादकता

सिंबाई जल उत्पादकता को फसल वृद्धि के दौरान किसान द्वारा अनुप्रयुक्त सिंबाई जल में फसल आउटपुट/सतही नहरों, टैंक, पोखर अथवा कुंओं और टयूबवैल के माध्यम से सिंबाई प्रणाली, के अनुपात रूप में परिभाषित किया गया है। अत: सिंबाई एक अर्थिक गतिविधि है और किसान को जल उपयोग हेतु कुछ व्यय करना पड़ता है (कि.ग्रा./वर्ग मी.)। यह प्राकृतिक संकृतक है जो किसान द्वारा अनुप्रयोग में लाए गए वास्तविक सिंबाई जल के संबंध में प्राप्त फसल आउटपुट का आकलन करने में मदद देता है।

#### जल असुरक्षा सूचकांक

भारत की जल असुरक्षा सूचकांक दर्शाता है कि भारत का समुत्थानशिक्त का स्कोर बहुत कम है। वर्ष 2050 तक भारत विश्व में जल सुरक्षाहीनता का केंद्र बिंदु बन जाएगा। उधर अमेरिकी जल संसाधन संस्थान ने 2040 तक अमेरिका, चीन और भारत गंभीर जल संकट का सामना करेंगे। एशिया जल विकास परिदृश्य 2016 के अनुसार, भारत में लगभग 89 प्रतिशत भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है और इस बात पर गहरी चिंता जताई जा रही है कि क्या इस प्रकार भूजल का उपयोग करने की यह जारी प्रथा धरणीय रह पाएगी, क्योंकि भूजल की गहराई धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है।

#### महिला कृषकों की बढ़ती संख्या

महिलाएं फसल उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, कटाई के बाद के कार्यकलाप, कृषि/सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन इत्वादि सहित कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार, महिलाओं द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कार्यशील जोतों का हिस्सा वर्ष 2005-06 में 11.7 प्रतिशत

- कृषि वस्तुओं की मूल्य नीति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा जनवरी 1965 में किसकी अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई?
   एम.एल, दांतेवाला
- केंद्र सरकार ने किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) कर दिया?
- केवल चाय, कॉफी, रबड़ एवं तम्बाकू के किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष स्कीम (Price Stabilisation Fund Scheme) की शुरुआत कब की गई?
   अप्रैल 2003
- 21 जनवरी, 2004 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का उद्घाटन किया गया। किसान कॉल सेंटर देश के कितने महानगरों में स्थापित किया गया है? - 8 महानगर
- किसान कॉल सेंटर से किसान नि:शुल्क किस नम्बर पर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं?
- जनवरी 2004 से प्रारंभ कृषि चैनल का संचालन कीन-सी संस्था करती है? इन्न्
- वित्तीय वर्ष 2005-06 में नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण ज्ञान केंद्र स्थापित करने की योजना शुरू की गई। इन केंद्रों के लिए किस कोष से धन उपलब्ध कराया जाता है?
   ग्रामीण आधारिक संरचना कोष
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत वर्ष 2005-06 में एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में किया गया। गठन किया गया। वर्ष 2014-15 में इसको किस मिशन में सम्मिलत कर दिया गया?
   - समन्वित बागवानी विकास मिशन (MIDH)
- देश में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत अक्टूबर 2006 में गई। यह किस मंत्रालय की पहल है?
   कृषि मंत्रालय
- नेशनल कमॉडिटी एवं डेरीवेटिव स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कृषिगत उत्पादों के लिए देश का पहला कमॉडिटी सूचकांक 3 मई, 2005 को बनाया गया। इसको किस नाम से जाना जाता है?

  - NCDEX.AGRI
- राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) के तहत बारहवीं योजना अविध की समाप्ति तक भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन तथा डिजिटलीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था?
- भारत में वर्ष 2017-18 में सभी तीन प्रकार के उर्वरकों (नाइट्रोजनयुक्त, फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरक) का उत्पादन, आयात और उपभोग क्रमश: 18109, 8530 और 26591 हजार टन रहा। इनमें से किस उर्वरक का उत्पादन, आयात और उपभोग सर्वाधिक था?
  नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक (अधिकांशत: युरिया)
- कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, भारत में उर्वरक का मानक अनुपात 4:2:1 होना चाहिए,
   परंतु यह कितना है?
   6,5:2,5:1
- उर्वरक सब्सिडी को अब सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाने (डीबीटी) की पहल की गई है। वर्तमान में वार्षिक उर्वरक सब्सिडी लगभग कितनी है?

- 70 हजार करोड़ रुपये

- ग्यारहवीं योजना में सार्वजनिक निवंश को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2007-08 में किस योजना की श्रुरुआत की गई?
   राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
- भारत में किस कार्ययोजना के तहत सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) की शुरुआत की गई है?
   - राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (2008)

से बद्दकर 2015-16 में 13.9 प्रतिशत हो गया। महिला किसानों द्वारा संचालित सीमांत एवं छोटी जोतों का अंश बद्दकर 27.9 प्रतिशत हो गया है।

#### कृषि में ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी

कृषि वाजारों में व्याप्त सुचना अंतर को पाटने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग इसका एक उदाहरण है। कॉफी बोर्ड ब्लॉक चेन आधारित बाजार एप्लिकेशन का विकास करने का प्रयास कर रहा है। इस प्लेटफार्म पर भारत और विदेशों के कॉफी कृषक, निर्यातक, आयातक व खुदरा विक्रंता पंजीकृत किए चुके हैं। भारत विश्व में फ्रांस और इधियोपिया के बाद कुछ कॉफी ब्लॉक चेन संसाधकों में से एक है। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत, वितरित और सार्वजनिक डिजिटल लेजर है, जिसका उपयोग कई कंप्यूटरों में लेन-देन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है ताकि किसी भी शामिल रिकॉर्ड को पूर्ववर्ती सभी ब्लॉकों कं परिवर्तन के विना पूर्वव्यापी रूप से बदला नहीं जा सके।

# कृषि विपणन और कृषक अनुकृल सुधार संकेतक

आदर्श कृषि उत्सद बाजार समिति अधिनियम (APMC Act) के सात उपबंधों के कार्यान्वयन, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार पहल, विपणन के लिए फलों व सिक्वयों के विशेष उपचार और मीडियों में विधिन्न करों के आधार पर नीति आयोग ने वर्ष 2016 में 'कृषि विपणन और कृषक अनुकृल सुधार सूचकांक' (AMFFRI: Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Index) तैयार किया, जिसमें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है। इन संकेतकों से कृषि व्यापार करने में सरलता के साध-साध, कृषकों को आधुनिक व्यापार व वाणिज्य से लाभान्वित होने के अवसर भी प्राप्त होते हैं तथा उनके

### किरण NCERT अर्थव्यवस्था सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- पूर्वी भारत, जिसके अंतर्गत सात राज्य नामत: असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़िशा, पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते हैं, में हरित क्रांति लाने की प्रक्रिया कब आरम्भ की गई?
- सिंचाई परियोजनाओं को वृहद, मध्य एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लघु सिंचाई परियोजना के लिए कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर या उससे कम एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2000 से 10,000 हेक्टेयर होता है। वृहद सिंचाई परियोजना का कमांड क्षेत्र कितना होता है? - 10,000 हेक्टेयर से अधिक
- सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की शुरुआत 1995-96 में की गई। केंद्र सरकार ने अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1996-97 में किस कार्यक्रम की शुरुआत की? - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के साथ 1974-75 में प्रारंभ किए गए किस कार्यक्रम को समावोजित किया गया है, तार्कि पूर्व में सृजित सिंचाई क्षमताओं का उपयोग किया जा सके?
   कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- वर्षा सिंचित क्षेत्रों में किसानों की आय के संवर्धन के उद्देश्य से वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी) की शुरुआत किस योजना की एक उप-योजना के रूप में की गई है?
   राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मेंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की सिमित (सीसीईए) ने किस योजना को 2 जुलाई, 2015 को मंजूरी प्रदान की?
   प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)
- धान और गन्ना देश में सिंचाई हेतु उपलब्ध जल का कितना हिस्सा लेते हैं जिससे अन्य फसलों के लिए कम पानी उपलब्ध रह जाता है? - 60% से भी अधिक
- खाद्यान्न भंडारण की कुल उपलब्ध क्षमता 727 मीट्रिक टन है, जो अपर्याप्त है। उचित भंडारण न होने के कारण खाद्यान्न बर्बाद हो जाते हैं। भंडारण एवं वितरण की नीतियों की समीक्षा के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? - शांता कुमार कमेटी
- फलों-सब्जियों के शीत भंडारण की क्षमता कितनी है? उत्पादन का 10 प्रतिशत
- खराब होने वाले कृषि बागवानी उत्पादों के मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार-हस्तक्षेप को
  सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने केंद्रीय योजना के रूप में मूल्य
  स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की शुरुआत कव की?
   मार्च 2015 में
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के स्रतगढ़ करने में किस योजना का शुभारंभ किया? - मुदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
- किसानों को मृदा स्वास्थ्य को जानने तथा मृदा पोषक तत्वों (उर्वरकों) के विवेकपूर्ण चयन में मदद करने के लिए इस योजना के तहत तीन साल में कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जायेंगे?
   14 करोड़
- भारत चीनी का विशाल उपभोक्ता तथा ब्राजील के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उत्पादनकर्ताहै।
   यह किस अधिनियम द्वारा अधिनियमित है? आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
- बाजार सुधार के मार्ग पर चलते हुए सरकार ने 2013 में चीनी उद्योग को विनियंत्रित कर दिया। चीनी वर्ष क्या है?
   - सितंबर-अप्रैल
- देश में श्वेत क्रांति लाने के लिए पशु मालिकों को पशुपालन के सुधरे तरीकों का पैकेज प्रदान करने के लिए 1964-65 में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई?
  - सधन पशु विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन कब किया गया?
 - 1965 में

सापने अपनी फसल की बिक्री के लिए वृहत विकल्प मिल जाते हैं। इन संकेतकों से कृषि बाजारों में होने वाली प्रतिस्पर्धा, दक्षता व पारदर्शिता का भी पता चलता है। इसमें दिए जाने वाला न्यूनतम अंक सून्य है जिसका अर्थ है कि किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया है तथा अधिकतम अंक 100 है जिसका तात्पर्य है कि चयनित क्षेत्र में पूर्ण रूप से सुधार किया गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को संकेतक के प्राप्तांकों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2016 में इसकी सूची में महाराष्ट्र पहले, गुजरात दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर था।

## राष्ट्रीय गोकुल मिशन

24 जुलाई, 2014 को क्डॅ सरकार ने स्वदंशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य देशी नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम आयोजित करना है ताकि आनुवॉशक शारीरिक गठन को सुधारा जा सके और स्टॉक में वृद्धि की जा सके। ज्ञातव्य है कि देशी पशु गर्मी सहन करने और चरम जलवायु संबंधि स्थितियों को झेलने की धमता की अपनी गुणवत्ता के लिए बखुवी जाने जाते हैं।

#### ई-पश्हाट पोर्टल

राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन स्कीम कं अंतर्गत गुणवत्ता को गोजातीय जनन-द्रव्य की उपलब्धता कं संबंध में प्रजनकों और किसानों को जोड़ने के लिए ई-पशुधन हाट पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल कं माध्यम से प्रजनक/कृषक अपने प्रजनन स्टॉक का क्रय-विक्रय कर सकते हैं। सभी किस्म के जनन-द्रव्यों और वीर्य भूण और पशुधन तथा देश में सभी एजोंसयों व पणधारियों से संबंधित सूचना पोर्टल पर अपलोड की गई है।

- ऑपेरशन फ्लंड कार्यक्रम का संबंध दुग्ध उत्पादन से हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लंड का सूत्रधार किसको माना जाता है?
   डॉ. वर्गीज क्रीयन
- ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है।
   राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई? वर्ष 1970
- ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को तीन चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1970 से 1980 तक और दूसरा चरण 1981 से 1985 तक था। तीसरा चरण कब से कब तक रहा?
  - वर्ष 1985 से 1996 तक
- ऑपरेशन फ्लड के परिणामस्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर आ गया है?
- विश्व में दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत के बाद दूसरे स्थान पर कीन-सा देश है?
   संयुक्त राज्य अमेरिका (करीब 87 मिलियन टन)
- भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल गया?
- भारत विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन का 20 प्रतिशत उत्पादन करता है। यह दुग्ध उत्पादन के मामले में लगातार प्रगति कर रहा है, 1991-92 में दुग्ध का उत्पादन 55.6 मिलियन टन था जो बढ्कर (4.5 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि) वर्ष 2018-19 में कितना हो गया?
- अखिल भारतीय स्तर पर देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 375 ग्राम है। असम में दूध की उपलब्धता सबसे कम प्रतिदिन 71 ग्राम प्रति व्यक्ति है। भारत में सर्वाधिक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता किस राज्य में है?

- पंजाब ( 1120 ग्राम )

प्रमुख पशुधन उत्पाद और मछली उत्पादन								
वर्ष	वृध (मिलियन टन)	अंडे (मिलियन नग)	मछली (हजार टन)					
1950-51	17.0	1832	752					
1960-61	20.0	2881	1160					
1970-71	22.0	6172	1756					
1980-81	31.6	10060	2442					
1990-91	53.9	21101	3836					
2000-01	80.6	36632	5656					
2010-11	121.8	63024	8400					
2011-12	127.9	66450	8700					
2012-13	132.4	69731	9040					
2013-14	137.7	74752	9572					
2014-15	146.3	78484	10164					
2015-16	155.5	82929	10795					
2016-17	165.4	88137	11420					
2017-18	176.3	95217	12590					
2018-19	187.7	103318	13420					

#### राष्ट्रीय पश्चन मिशन

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) वितीय वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य पशुधन उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करना है। चारे और उसके विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस योजना में कहा गया है कि एनएलएम के तहत चारा और चारा विकास उप-मिशन पशु चारा संसाधनों की कमी की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाती है ताकि भारत के पशुधन क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाया जा सके और निर्यात क्षमता का उपयोग किया जा सके।

#### जलवायु स्मार्ट कृषि

जलवायु स्मार्ट कृषि (सीएसए) एक ऐसा दृष्टिकाण है, जो वदलती जलवायु में प्रभावकारी रूप से विकास को समर्थन देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में कृषि प्रणालियों को वदलने और पुन: नया बनाने के लिए आवश्यक कृत्यों का मार्गदर्शन करने में सहायता करता है। सीएसए का उद्देश्य निम्न तीन मुख्य लक्ष्यों को पूरा करना है— 1. कृषि उत्पादकता और आय को सतत रूप से बढ़ाना; 2. जलवायु परिवर्तन के संबंध में अनुकृलता को अंगीकार करना; 3. ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना/ समाप्त करना।

#### वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक

वंशिवक खाद्य सुरक्षा सूचकां क (जीएफएसआई), 2019 के अंतर्गत विश्व के 113 देशों में खाद्य सुरक्षा के चार मुख्य मुद्दों पर विचार किया गया-अर्थ वहनीयता, उपलब्धता, गुणवत्ता एवं सुर्रक्षित होना और प्राकृतिक संसाधन एवं लचौलापन। जीएफएसआई उक्त प्रथम तीन श्रेणियों के आधार पर विभिन्न देशों को 0-100 तक के स्कोर में अनुक्रम प्रदान करता है, जबिक प्राकृतिक संसाधनों एवं लचौलेपन का उपयोग एक समायोजन गुणक

# िनरण NCERT अर्थव्यवस्था सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- दुग्ध देनेवाले पशुओं की उत्पादकता में सुधार, दुग्ध अर्जन हेतु ग्रामीण स्तरीय मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ एवं विस्तारित करने तथा डेयरी क्षेत्र में उत्पादकों को बाजार में बेहतर पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से मार्च 2012 में किस योजना की शुरुआत की गई?
  - राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-1
- सरकार ने देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अविध के दौरान किस योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमोदन दिया है?

- राष्ट्रीय डेयरी योजना ( एनडीपी )

- दिल्ली के निवासियों को उचित कीमत पर पौष्टिक दूध उपलब्ध कराने व दुग्ध उत्पादकों को अच्छी कीमत दिलवाने के उद्देश्य सेदिल्ली दुग्ध योजना (DMS) की शुरुआत कब की?
- नेशनल प्रोजेक्ट फाँर कैटल एंड बफोलो ब्रीडिंग की शुरुआत भारत में कब की गई?
   वर्ष 2000
- वर्ष 2001-02 में कृषि निर्यात को बदावा देने के लिए भारत के 7 राज्यों में 8 कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित करने की योजना बनायी गई। इस योजना के अंतर्गत वासमती चावल के निर्यात के लिए देश का पहला कृषि निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया?
- वर्तमान में भारत के 20 राज्यों में कुल कितने कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित हैं?
   कुल 60
- कृषि व खाद्य निर्यात के मामले में विश्व में भारत किस स्थान पर है?
   10वें स्थान पर
- 2017-18 में समाप्त होने वाले पिछले 6 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र
   में कितने प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है? लगभग 5.6 प्रतिशत
- भारत के प्रसंस्कृत खाद्य प्रदार्थों का कुल निर्यात 330.08 विलियन डॉलर के बरावर हुआ। यह भारत के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है? - लगभग 10,70 प्रतिशत
- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद-निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) कृषि निर्यात क्षेत्रों के संबंध में केंद्र सरकार की शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई?
   वर्ष 1986 में
- चाय उत्पादन में (विश्व का 29 प्रतिशत) भारत का कीन-सा स्थान है? पहला
- 'अन्न बचाओं अभियान' कब प्रारम्भ किया गया? -1965-66 में
- कृषि के आधुनिकीकरण और कृषि वर्बांदी को कम करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई? - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (इस योजना के परिणामस्वरूप खंत से लेकर खुदरा विक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सुजन होगा। इससे न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति प्राप्त होगी बल्कि यह किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय को दुगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भारी अवसरों का सृजन करने, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।)
- मेगा फूड पार्क बोजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पदन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना है ताकि मूल्यवर्धन को अधिकतम, बर्बादी को न्यूनतम, किसानों को आय में वृद्धि और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना सुनिश्चित किया जा सके। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई?
- भारत में सबसे बडा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कीन-सा है? बेकरी

कं रूप में किया जाता है। 100 अंकों के अनुक्रम को सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। वीएफएसआई का मुख्य लक्ष्य एक समयबद्ध रीति से यह आकलन करना है कि किन देशों में खाद्य असुरक्षा की संभावना सबसे अधिक है और किनमें सबसे कम है। भारत का समग्र खाद्य सुरक्षा स्कोर 100 में से 58.9 है और 113 देशों में 72वीं रैंक है जो भारत के लिए विभिन्न पहलुओं से खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन में और सुधार की आवश्यकता को रेखाँकित करती है। पहले स्थान पर सिंगापुर है, जिसका खाद्य सुरक्षा स्कोर 87.4 है।

# परिचालन जोत

परिचालन जोत वह भूमि है, जिसका उपयोग अंशत: या पूर्णत: कृषि उत्पादन के लिए किया जाता है, इसमें किचन, गार्डन या पशुपालन संवृद्धि के लिए प्रयुक्त भूमि शामिल है। किंतु सहकारी खेती और संस्थानिक स्वामित्व को इससे बाहर रखा गया है।

#### राष्ट्रीय कृषि वाजार

राष्ट्रीय कृषि वाजार (एनएएम) एक राष्ट्रीय स्तर का इलंक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाजार है, जिसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार बनाना है। एनएएम के पीछे स्थानीय कृषि उपज मंडी समित रहेगी।

#### जीएम बीज

जब किसी पौधे के प्राकृतिक जीन में कृत्रिम उपायों द्वारा उसकी मूल संरचना में परिवर्तन कर दिया जाता है, जो ऐसे पौधे से प्राप्त बीज को जीएम बीज (Genetically Modified Seeds) कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य फसलों को रोगों और कीटों द्वारा फसलों को होने वाली हानि से बचाना, रासायनिक तत्वों के इस्तेमाल में कमी

- 20वीं पशु गणना, 2019 के अनुसार, भारत में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है। इसमें वर्ष 2012 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है?
   मात्र 4.63%
- पशु गणना, 2019 के मुताबिक भारत में मादा मवेशियों (गायों) की संख्या 2012 की तुलना में 18% बढ़कर वर्ष 2019 में कितनी हो गयी?
   145,12 मिलियन
- वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पशुओं की कुल संख्या के लिहाज से प्रथम तीन राज्य कौन-कौन से हैं?
   उत्तर प्रदेश (67.8 मिलियन),
  - राजस्थान (56,8 मिलियन) और मध्य प्रदेश (40,6 मिलियन) भारत में पशुओं की गणना वर्ष 1919 में शुरू हुई थी। उसकेबाद से ही कितने वर्ष
- भारत विश्व में सबसे बड़ा पशुधन संख्वा वाला देश है। विश्व के कुल पशुधन संसाधनों का लगभग 10.7 प्रतिशत हिस्सा है। इसके पास विश्व के कितने प्रतिशत भैसें हैं?

पर यह गणना की जाती है?

- मात्र ५६ ८ प्रतिशत

- पांच वर्ष पर

(भारत की 19वीं पशुधन गणना के अनुसार, भारत के पास पशुधन के विशाल संसाधन है जिसमें लगभग 300 मिलियन मवेशी, 65.07 मिलियन भेड़, 135.2 मिलियन बकरियां और 10.3 मिलियन सुअर शामिल है।)

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की 70वें दौर के अनुसार, ग्रामीण लोगों की कितनी आबादी का मुख्य आय स्रोत पशुपालन था?
   लगभग 3.7%
- भेड़ और वकरी को सामूहिक तौर पर लघु-पशुधन के रूप में जाना जाता है। विश्व के कुल भेड़ों में से 6.4 प्रतिशत भेड़ भारत में पाए जाते हैं (खाद्य एवं कृषि संगठन) । देश में कुल पशुओं की आबादी 512.1 मिलियन है, जिसमें से वकरी एवं भेड़ की आबादी 200 मिलियन है जो देश के कुल पशुधन की आबादी का 39 प्रतिशत है। विश्व में पायी जाने वाली कुल बकरियों की आबादी में से कितनी प्रतिशत बकरियां भारत में पायी जाती हैं? - मात्र 16.1 प्रतिशत
- देश में मास्स्यकी उप-क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय मास्स्यकी विकास बोर्ड की स्थापना कब की?
- मछली पालन उद्योग भारत में तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जो 14.5 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को आय और रोजगार प्रदान कराने के अतिरिक्त देश की एक बड़ी आबादी को पोषण और खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। विश्व में सबसे बड़े मछली उत्पादक देशों में भारत का कौन-सा स्थान है?
- वर्ष 2018-19 में भारत में कुल मत्स्य उत्पादन लगभग 13420 हजार मीट्रिक टन था।
   उसमें स्थलीय सेक्टर का योगदान कितना है?
   करीब 70 प्रतिशत
- कौन-से राज्य प्रगतिशील रूप शून्य वजट प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहे हैं,
   जिससे इन राज्यों में आदान लागतों में भारी कमी आई है और पैदाबार में वृद्धि हुई
   है?
   कनॉटक, हिमाचल प्रवेश और आंध्र प्रवेश
- कॉफी बोर्ड ने किस प्रौद्योगिकी पर आधारित ई-बाजार का शुभारंभ किया है, जिससे कृषकों को बाजारों से पारदर्शी रीति से जोड़ने में सहायता मिल सकेंगी और परिण गामस्वरूप कॉफी उत्पादकों को उचित कीमत प्राप्त हो सकेंगी?

- ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी

- भूमंडलीकरण कृषि उत्पाद के निर्यात का नया अवसर लेकर आया है। इसके चलते कृषि में बड़े निवेश की जरूरत महसूस हुई है। भारत ने कृषि को उद्योग का दर्जा कब दिया?
- 2013 में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में 75 प्रतिशत ग्रामीण एवं 50 प्रतिशत शहरी आबादी को शामिल किया गया है। इसमें किस दर पर अनाज मिलता है? — चावल, गेहुं एवं मोटा अनाज क्रमश: 5, 3 और 1 रुपये पर

लाना और फसली पौधों में वातावरण के प्रांत दवाव को सहने की क्षमता विकसित करने में मदद पहुंचाना है। इन बीजों और फसलों के साथ कुछ हानियां और जोखिमें भी जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से इसका विरोध भी हो रहा है। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल आदि इसके उदाहरण हैं।

#### डिप सिंचाई प्रणाली

हिए सिंचाई नियोंत्रत सिंचाई की एक विधि है, जिसमें पाइप और द्यूव के माध्यम से पानी को धीरे-धीरे पौधों की जड़ प्रणाली तक पहुंचाया जाता है। इस विधि में पानी या तो मिट्टी की सतह पर जड़ों के ऊपर या सीधे जड़ क्षेत्र में टपकाया जाता है। यह सिंचाई प्रणाली वाष्मीकरण और अपवाह को कम करने और जल संरक्षण करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा, द्रिप सिस्टम सिंचाई के पानी में तरल उर्वरक को भी शामिल किया जा सकता है। इस प्रणाली में पानी की वचत होती है और प्रति हंक्टेयर उपज भी अधिक प्राप्त होती है।

#### फर्टिंगेशन प्रणाली

फार्टिगेशन उर्वरकों का इंजेक्शन है, जिसका उपयोग मुदा संशोधन, जल संशोधन और जल में अन्य घुलनशील उत्पादों को सिंचाई प्रणाली में शामिल करने के लिए किया जाता है। इस प्रणाली के तहत पौधों या फसलों को पोषक तत्व सिंचाई के माध्यम से दिए जाते हैं। इस विधि के प्रयोग से उर्वरक की 25% की बचत होती है तथा पोषक तत्वों का पूर्ण उपयोग होता है।

#### ग्रामीण कृषि बाजार

86% से ज्यादा लघु और सीमांत किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए मौजूदा 22 हजार ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (GrAMs) के रूप में विकसित तथा उन्तत किया जायेगा।

### िन्या MCERT अर्थव्यवस्था सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- एनएफएसए में महिलाओं एवं बच्चों को पोषण समर्थन प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें कितनी ग्रिश का मातृत्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान है?
   6000 रुपये
- मौसम के वारे में अगले पांच दिनों के लिए पूर्वानुमान, निकटतम शहर में वस्तुओं और फसलों के बाजार मूल्य, उर्वरक, बीज, मशीनरी आदि पर ज्ञान प्रदान करने वाले किस एप्प की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 19 मार्च, 2016 को की गई? - किसान सुविधा
- 1995 में स्थापित डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के अनुसार, कृषि क्षेत्र को सरकार द्वारा दी जाने वाली खूट सकल कृषिगत उत्पाद के 10% से अधिक नहीं होगी। डब्ल्यूटीओ की शब्दावली में कृषि खूट को पेटियों (Boxes) के रूप में सम्बोधित किया गया है।इनको किन तीन नामों से जाना जाता है? एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्ल्यू बॉक्स
- किस कमेटी ने कृषि भूमि को पट्टे पर देने और प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सिफारिश की है?
   टैठ कमेटी
- प्रमुख बाजारों को एकजुट करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट स्कीम (आरईएमएस) नामक सफल प्रयोग कहां किया गया है?
- कृषि कल्याण उपकर सभी सेवाओं पर लागू है। इसका पूरी तरह से उपयोग कृषि और किसान कल्याण से संबंधित गतिविधियों से संबंधित वित्तपोषण में किया जाता है। यह उपकर कितना हैं?
- केंद्र सरकार द्वारा 2015 में पाम ऑयल खेती में स्वचालित मार्ग के माध्यम से कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमित है?
   शत प्रतिशत
- राष्ट्रीय बांस कार्यक्रम देश में बांस की फसल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। यह किस मंत्रालय की पहल है?
   कृषि मंत्रालय
- 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने 24 फरवरी, 2019 को किस योजना की शुरुआत की, जिसके तहत दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को वार्षिक 6000 रुपये देने की बात कही गई?

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

- (नोट: अब दो हंक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों के बजाय इस योजना के तहत सभी भूमि मालिकों को शामिल कर लिया गया है। पहले इसके तहत 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलने वाला था, लेकिन अब 14.5 करोड़ किसान इसके दायरे में आ गए हैं। पहले प्रतिवर्ष इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपये खर्च होना था, लेकिन अब 87,000 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे।)
- उस कृषि को क्या कहा जाता है, जिसमें पर्यावरण पर बिना प्रतिकृल प्रभाव डालेकृषि
  विकास किया जाता है तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे पोषण चक्र, नाइट्रोजनस्थिरीकरण
  आदि पर बल दिया जाता है?
   धारणीय कृषि (Sustainable Agriculture)
- भारत में वाणिज्यिक कृषि के लिए स्वीकृत एकमात्र जीएम फसल बी कॉटन है। इसकी बुआई में भारत का स्थान विश्व में कौन-सा है?
   - चौधा
   (नोट: उल्लेखनीय है कि फरवरी 2010 में केंद्र सरकार ने बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी थी।)
- भारत में बीटी कॉटन के बीजों की आपूर्ति करने वाली दो कम्पनियां हैं। पहली कम्पनी
  गुजरात की महिको मॉसेंटो है। दूसरी कम्पनी है? रासी सिद्धस लि., तमिलनाद्व
- भारत में कृषि और खाद्य पदार्थों या उत्पादों पर लगाये जाने वाले प्रमाणनचिद्ध (1937 से लागू और 1986 में संशोधित) को क्या कहा जाता है? - एगमार्क (AGMARK)
- 'एगमार्क' किससे संबंधित है?
   कृषि विषणन से
- भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या होती है?
   1 जुलाई से 30 जून

#### ऑपरेशन ग्रीन्स

ऑपरेशन फ्लंड की तर्ज पर आलू, टमाटर और प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स प्रारम्भ करने का सरकार का प्रस्ताव है। इसके प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रुपये की राशि आर्वोटत की गई है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों, एग्री-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण केंद्रों और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। साथ ही किसानों की सहायता करना और क्षेत्रीय तथा मौसमी उत्पादों जैसे- प्याज, आल् एवं टमाटर की कीमतों में अनियमित उतार-चढाव को नियंत्रित तथा सीमित करने में मदद करना है। यह ऑपरेशन एक मुल्य स्थिरीकरण योजना है, जिसका लक्ष्य किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य दिया जाना सुनिश्चित करना है।

#### कृषि बाजार अवसंरचना कोष

22 हजार ग्रामीण कृषि बाजारों तथा 585 एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना कं विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये की स्थायीनिधि से एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष (एएमआईएफ) की स्थापना की जायेगी। एएमआईएफ प्रदेशों/ केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को 585 कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) एवं 10,000 ग्रामीण कृषि बाजारों में विपणन की ढांचागत व्यवस्था विकसित करने के लिए उनके प्रस्ताव पर वित्तीय छूट प्राप्त ऋण मुहैया कराएगा। राज्य हब एवं स्पोक प्रणाली एवं पीपीपी प्रणाली समेत उन्नत एकीकृत बाजार अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कृषि बाजार अवसंरचना कोष से सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इन ग्रामीण कृषि बाजारों में मनरेगा योजना एवं अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग कर भौतिक एवं आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ किया जायेगा।